[Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe]

the younger generation experimenting and innovating, and their creativity, skills and talents are for everybody to see. For this younger generation, aspirational India needs to be further strengthened. In this regard, what is also required is to provide avenues for the young aspirational generation to travel around and visit successful and model or replicable development projects undertaken by both, Government and non-Government agencies.

Today, private and Government tour operators do not provide any opportunity to visit centres of scientific advancement, infrastructure marvels, or social work projects undertaken by voluntary organisations. Many Government departments do undertake several development projects which people may want to visit and learn about so that they have a sense of participation. Such on-the-spot study opportunities are rare, if not almost unavailable. Projects by Departments like Railways, Energy, Ports, Petroleum and Natural Gas, Space and Earth Sciences as well as Mining, Industry and even Rural and Village Industries are required to be showcased to achieve two specific objectives. Firstly, facilitating such Development Tourism would serve creating a strong sense of participation amongst the people at large. Secondly, it would give further impetus to the process of educating people at enhancing the level of Governance Literacy. Sir, we have seen the fire brigade operating. But, we never go and see as to how the Fire Department operates or, for that matter, the Telecom Department, or how horticulture and food processing take place in very nook and corner of our country or as to how the Meteorological Department operates. People are required to get more knowledge about it. Therefore, these facilities are required. While raising this issue, I call upon the Government to explore the possibility of opening up a Department of Development Tourism under the Ministry of Tourism.

SHRI AJAY SANCHETI (Maharashtra): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): सर, मैं भी अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): सर, मैं भी अपने को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

Alleged injustice meted out to the Ravidasiya community in Punjab

श्री शमशेर सिंह दुलो (पंजाब): सर, पिछले दो सालों से हिंदुस्तान में, जहां धर्म के नाम पर कुछ स्टेट्स में सरकारें राज कर रही हैं, दलित, मजदूर और गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। चाहे वह गुजरात की घटना हो, चाहे वह मध्य प्रदेश में मंदसौर की घटना हो, एटा की घटना हो। ऐसे ही पंजाब में कांडा का कांड हुआ। सर, 24 मई, 2009 में वियना में रबिदासिया समाज के धर्म गुरु डेरा बलां के रामानंद और संत नरिंजन दास जी पर sikh militants ने वहां के एक गुरुद्वारे पर हमला कर रामानंद

जी की हत्या की, नरिंजन दास जख्मी हुए। सर, न सिर्फ पंजाब में बल्कि देश के different states में उनकी हत्या के विरोध में धरने और protests हुए। उन protests में न केवल दलितों ने हिस्सा लिया बल्कि बाकी धर्मों के लोग, जो डेरा बलां के ऊपर श्रद्धा रखते थे, उन सभी ने न केवल पंजाब में बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी धरने दिए।

सर, मैं मानता हूं कि मौजूदा सरकार ने नादिरशाही हुक्म कर के 2013 में एक कमीशन बनाया और उस कमीशन ने यह ऑर्डर पास किया और जो innocent लोग हैं, जो डेरा बलां के साथ संबंध रखते हैं, उन पर 700 करोड़ रुपए के damages का भार उन पर डाला जा रहा है। वह उन के रिकवर करने की कोशिश की जा रही है।

सर, देश में धरने दिए जाते रहे हैं, चाहे वह किसानों का धरना हो, चाहे जंतर-मंतर पर हो या देश में कहीं भी धरने दिए जाते हैं, लेकिन यह बीजेपी व अकाली सरकार का पहला नादिरशाही हुक्म है, जिसको सेंटर की सरकार का protection है, उसने डेरा बलां के अनुयाइयों पर false cases किए हैं। अभी भी 500-600 लोगों पर अदालतों में false केस चल रहे हैं और 700 करोड़ रुपए डेरा बलां के अनुयाइयों से वसूल करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह बहुत ही नादिरशाही हुक्म है। मैं आपके जरिए देश की सरकार को कहना चाहता हूं कि वह intervene करे और इसे रोके। देश में शांति बहाल करने के लिए यह जरूरी है क्योंकि आप सेंटर में रूलिंग करते हैं। आगे भी ऐसे लोगों के sentiments उभारने की कोशिश होती रही है। ऐसे नादिरशाही हुक्म दलितों पर क्यों हों? सर, यहां किसानों के धने होते हैं, different castes के लोगों के धरने होते हैं, उनसे मुआवजा क्यों नहीं लिया जाता? रेलवे की और दूसरी सरकारी प्रॉपर्टीज फूंक दी जाती हैं, फिर दलितों पर ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? उनसे ही रिकवरी क्यों की जा रही है? मैं सेंटर की सरकार को हिंदुस्तान के दलितों की तरफ से एक चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे नादिरशाही हुक्म आप करेंगे ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Your time is over. Now, Mr. Naresh Agrawal.

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं इस विषय से अपने आप को संबद्ध करता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं भी इस विषय से अपने आप को संबद्ध करता हूँ।

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RANJIB BISWAL (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI P.L PUNIA (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. Now, Shri Naresh Agrawal. ...*(Interruptions)*... Your time is over. ...*(Interruptions)*... The names of all the hon. Members, who have associated themselves with it, may be included. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Naresh Agrawal.

Concern over increasing road accidents due to absence of an effective road safety system

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): सर, हर साल सड़क दुर्घटनाओं में देश में करीब डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं, जिस में 50 परसेंट नौजवान होते हैं। सर, overloading से भी करीब 25000 लोगों की हर साल डेथ होती है। हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी देश में नेशनल हाइवे बनाने की घोषणा करते हैं। एनएचएआई ने पेट्रोल, डीज़ल पर सेस भी लगाया है ताकि देश में सड़कों का निर्माण हो। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल : लेकिन उस cess से रोड़ सेफ्टी सिस्टम को डेवलप नहीं किया जा रहा है। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, तो वहाँ स्पीड हमसे दोगुनी है, अगर कहीं धोखे से accident हो जाए, तो फौरन क्रेन आएगी, trauma centre available है, ambulance available है, लेकिन हमारे देश में क्या है? क्या कहीं भी रोड़ सेफ्टी सिस्टम है? श्रीमन्, आज accident हो जाए, तो accident करने वाला अगर यह चाहता है कि जिसका accident हुआ है, वह उसको हॉस्पिटल पहुँचा दे, तो वह उसे इस डर से हॉस्पिटल नहीं पहुँचाता है कि कहीं उसको जनता पीट-पीट कर मार न दे, क्योंकि कोई protection नहीं है। जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, तो रोड़ सेफ्टी सिस्टम के ऊपर कई मीटिंग्स हुई थीं, भारत सरकार से भी मीटिंग्स हुई थीं और यह तय हुआ था कि देश में हर 50 किलोमीटर पर एक trauma centre होगा, डॉक्टर्स होंगे, रोड सेफ्टी पुलिस होगी, पुलिस की वैन होगी, क्रेन होगी, ambulance होगी, लेकिन यह कभी implement नहीं हुआ। आज यह हालत है कि हर तीसरा ड्राइविंग